REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 9 | JUNE - 2025

शहरीकरण: भारत के बड़े शहरों पर प्रभाव के सन्दर्भ में

डॉ. कल्पना कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग ,
कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय.

सारांश

शहरीकरण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। ग्रामीण शहरी प्रवासन को शहरीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। विकासशील देशों में शहरीकरण के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, गरीबी, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक असमानताओं से संबंधित कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। इन चुनौतियों के लिए व्यापक और टिकाऊ समाधानों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर सभी निवासियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हुए विकसित और समृद्ध हो सकें।

कई विकासशील देशों में, सरकारें बड़े शहरों और उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जो आमतौर पर घरेलू बाजारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी नियंत्रित करते हैं।ग्रामीण इलाकों को दी जाने वाली सौम्य उपेक्षा और उदासीनता ग्रामीण आबादी को गरीब बनाती है।बढ़ती आबादी, बढ़ती ग्रामीण भूमिहीनता, अत्यधिक विषम भूमि स्वामित्व, उर्वरकों की बढ़ती लागत, बीज और अन्य कृषि इनपुट की कमी और कृषि उपज से कम लाभ के कारण छोटे किसानों का जीवन कठिन हो गया है। उन्हें नौकरी, आजीविका और समृद्धि की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मुख्य शब्द :- शहरीकरण, बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण.

प्रस्तावना :-

शहरीकरण मुख्य रूप से 20 वीं सदी की घटना है ।पहली स्थायी मानव बस्तियाँ तब विकसित हुईं जब खानाबदोश लोगों ने फ़सल उगाना शुरू किया। खेती में क्रमिक प्रगति जैसे कि बोझा ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल और सिंचाई के विकास ने किसानों को प्रागैतिहासिक काल के नवजात गांवों और कस्बों को चलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करने में सक्षम बनाया। व्यापार के विविधीकरण और बहुत अधिक किस्म की वस्तुओं के उत्पादन

के साथ बड़ी संख्या में लोगों को उन जगहों पर बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगभग 5000 साल पहले (नवपाषाण काल) उपजाऊ क्षेत्रों में शहर विकसित होने लगे, जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था।

समृद्ध शहरी केंद्र जल्द ही संस्कृति और वाणिज्य के बीज बोने लगे। शहरों में मनुष्यों की सापेक्ष घनत्व ने विचारों और नवाचारों के आदानप्रदान को गति दी, जिस पर उस समय के विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी में प्रगति निर्भर थी। हालाँकि, ये शहर कभी भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे मुख्य रूप से अपने आसपास की फ़सल की उत्पादकता पर निर्भर थे। चूँकि परिवहन मुख्य रूप से बोझा ढोने वाले जानवरों पर निर्भर था, इसलिए उनकी आपूर्ति लाइनें छोटी थीं। नवपाषाण काल से ही दुनिया की आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण रही है। 1900 ई, तक दुनिया के केवल 14-12 % लोग ही शहरों में रहते थे।[1]

पिछली दो शताब्दी के दौरान शहरीकरण:

प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण तीव्र शहरीकरण हो रहा है। शहरी आबादी की प्राकृतिक वृद्धि दर ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के परिणामस्वरूप शहरों में उच्च उत्तरजीविता दर पाई जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आई है।[2,3] संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है, जिसमें कहा गया है कि देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गयी है। जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025: वास्तविक प्रजनन संकट" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या के लगभग 40 वर्षों में घटने से पहले इसके 170 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।[4,5,6]

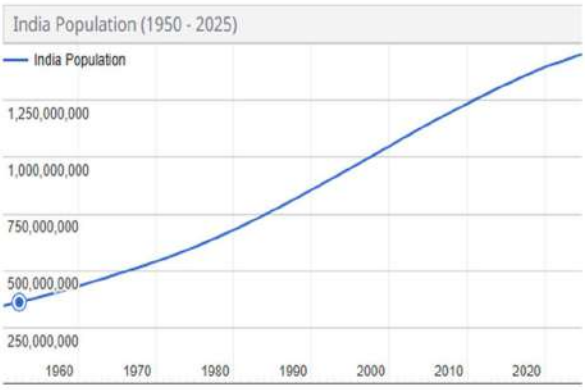

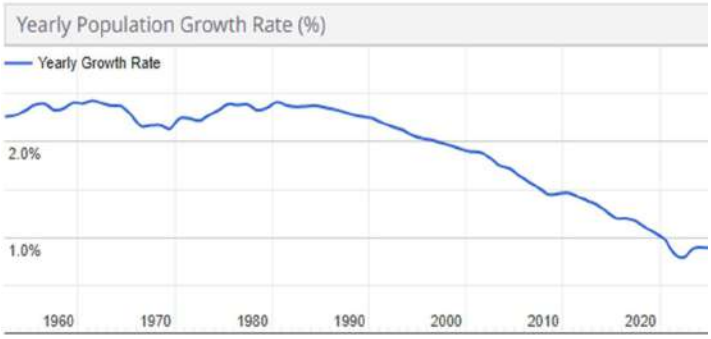

Source: **Worldometer** (www.Worldometers.info)

आज, शहर ग्रामीण इलाकों की कीमत पर फलते- फूलते हैं, जो सौम्य उपेक्षा का शिकार हैं। ग्रामीण इलाकों की गरीबी के कारण शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। त्वरित शहरीकरण शहरों के भीतर राजनीतिक शक्ति को केंद्रित करता है। इससे ऐसी नीतियाँ बनती हैं जो ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों को तरजीह देती हैं। सब्सिडी और मूल्य संरचना शहरी विकास के पक्ष में अधिक हैं, जो अक्सर शहरों में भोजन और अन्य बुनियादी वस्तुओं को सस्ता बनाती हैं। यह कृषि क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करता है जिससे ग्रामीण इलाकों को नुकसान होता है।औद्योगिक देशों में शहरों का विकास पहले से ही राष्ट्रीय आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। इन उद्योगों से होने वाले उत्पादन से देश समृद्ध होता है। विकासशील देशों में भी ऐसा ही रहा है, जब तक कि वहाँ समृद्ध और खुशहाल ग्रामीण इलाके हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की उत्पादकता एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे देश समृद्ध बनता है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती आबादी, बढ़ती भूमिहीनता और गरीबी लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करती है। शहरी क्षेत्र का अनियंत्रित विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर करता है ।आज बेलगाम शहरी विस्तार, कृषि विफलता का परिणाम है।[1]

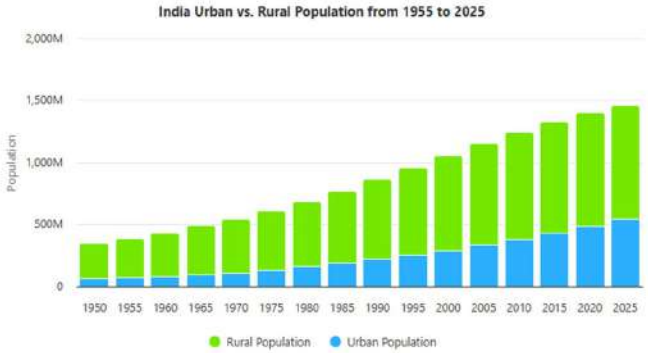

Source: **Worldometer** (www.Worldometers.info)

भारत में शहरीकरण के कारण:

शहरीकरण भारतीय समाज की एक आम विशेषता बन गई है। उद्योगों के विकास ने शहरों के विकास में योगदान दिया है। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों का विकास हुआ है। शहरों के विकास के कई कारण हैं। वे इस प्रकार हैं:[2]

औद्योगीकरण एवं व्यावसायीकरण:

औद्योगीकरण एक प्रवृत्ति है जो पुरानी कृषि अर्थव्यवस्था से नवीन गैर-कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक आधुनिक समाज का निर्माण करती है। भारत में औद्योगिकीकरण 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इसने देश की अर्थव्यवस्था और समाज को काफ़ी हद तक बदल दिया है। हालाँकि शुरुआती विकास धीमा था, लेकिन 1800 के दशक के अंत में इसमें तेज़ी आई और भारत अब एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था है। इस परिवर्तन के प्रमुख पहलुओं में कारखानों की स्थापना, तकनीकी प्रगति और आर्थिक गतिविधियों में बदलाव शामिल हैं। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से, बेहतर रोजगार के अवसरों के कारण अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए आकर्षित हुए हैं। औद्योगीकरण ने लोगों को आधुनिक क्षेत्रों में नौकरी में काम करने का मौका देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करती है।[2]

वाणिज्य और व्यापार शहरीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। व्यावसायीकरण और व्यापार के साथ यह सामान्य धारणा जुड़ी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कस्बे और शहर बेहतर वाणिज्यिक अवसर और लाभ प्रदान करते हैं।[2]

सामाजिक लाभ और सेवाएँ:

शहरों और कस्बों में जीवन के लिए कई सामाजिक लाभ हैं। उदाहरण के लिए बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर स्वच्छता और आवास, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर मनोरंजन सुविधाएँ और सामान्य रूप से बेहतर सामाजिक जीवन शामिल हैं। इस कारण, अधिक से अधिक लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक लाभ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए शहरों और कस्बों में प्रवास करने के लिए प्रेरित होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं।[2]

रोजगार के अवसर एवं जीवन शैली में बदलाव:

शहरों और कस्बों में रोजगार के भरपूर अवसर हैं जो लगातार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए, अधिकांश लोग अक्सर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों तक पहुँचने के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, खेल और मनोरंजन, उद्योग और व्यावसायिक उद्यमों जैसे सभी विकासात्मक क्षेत्रों में रोजगार के अनगिनत अवसर हैं। उद्योग उच्च मूल्य-वर्धित नौकरियाँ पैदा करते हैं और बढ़ाते हैं, इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।[2]

शहरीकरण की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे शहरी क्षेत्र अत्यधिक परिष्कृत संचार, बुनियादी ढाँचे, चिकित्सा सुविधाओं, ड्रेसिंग कोड, ज्ञान, उदारीकरण और अन्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता के साथ अधिक प्रौद्योगिकी-प्रेमी होते जा रहे हैं, लोगों का मानना है कि वे शहरों में एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में, लोग जीवन शैली में बदलाव को भी अपनाते हैं जैसे कि आवासीय आदतें, दृष्टिकोण, पहनावा, भोजन और विश्वास। नतीजतन, लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहर दिन-ब-दिन बढ़ती संख्या में लोगों को अपने में समाहित करके बढ़ते हैं।[2]

ग्रामीण शहरी परिवर्तन:

जैसेजैसे खनिज पदार्थों की खोज-, संसाधनों के दोहन या कृषि गतिविधियों के कारण इलाके अधिक उपजाऊ और समृद्ध होते जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की स्थिति बनने के साथ ही शहर उभरने लगते हैं। उत्पादकता में वृद्धि से आर्थिक विकास और उच्च मूल्यवर्धित रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर शिक्षा संस्थानों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर परिवहन नेटवर्क, बैंकिंग संस्थानों की स्थापना, बेहतर शासन और बेहतर आवास विकसित करने की आवश्यकता पैदा होती है। जैसेजैसे यह होता है-, ग्रामीण समुदाय शहरी संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते हैं और अंततः शहरी केंद्र बन जाते हैं जो बढ़ते रहते हैं क्योंकि अधिक लोग बेहतर जीवन की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाते हैं।[2]

भारत में शहरीकरण का प्रभाव :

शहरीकरण की उच्च दर के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरीकरण के प्रभाव को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैसकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। :[2]

सकारात्मक प्रभाव :

यदि शहरीकरण उचित सीमाओं के भीतर होता है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसलिए शहरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभावों में रोजगार के अवसरों का सृजन, तकनीकी और संरचनात्मक उन्नति, बेहतर परिवहन और संचार, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं और जीवन स्तर में सुधार शामिल हैं।[2]

नकारात्मक प्रभाव:

व्यापक शहरीकरण या शहरों के अंधाधुंध विकास के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। वे इस प्रकार हो सकते हैं:

अपर्याप्त आवास सुविधा:

आवास सुविधाओं की तीव्र कमी भारतीय शहरों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, चाहे वह महानगरीय शहर हो या छोटा शहर। भारत में शहरीकरण के कारण यह एक और गंभीर समस्या है। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसँख्या के कारण घरों की कमी की समस्या लगातार बनी रहती है। भारत में आधे से अधिक शहरी परिवार एक कमरे के घर में निवास करते हैं, जहाँ औसतन प्रति कमरा 4.4 व्यक्ति रहते हैं। देश भर में लगभग 13.7 मिलियन मलिन आवास हैं जो 65.49 मिलियन लोगों को आश्रय देते हैं। यह समस्या उन शहरी क्षेत्रों में अधिक गंभीर है, जहाँ बेरोजगार या कम रोजगार वाले अप्रवासियों का बहुत अधिक आक्रमण होता है। जिन्हें आसपास के क्षेत्रों से शहरों और कस्बों में आने पर रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। आवास समस्याओं के प्रमुख कारक हैं निर्माण सामग्री और वित्तीय संसाधनों की कमी, उप-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोगिताओं का अपर्याप्त विस्तार, शहरी प्रवासियों की गरीबी और बेरोजगारी, मजबूत जाति और पारिवारिक संबंध और उपशहरी क्षेत्रों में पर्याप्त परिवहन की कमी, जहाँ नए निर्माण के लिए अधिकांश उपलब्ध भूमि पाई जाती है। इसका कारण यह है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण की प्रक्रिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवास सुविधा की उपलब्धता और विकास में इतनी तेजी से विस्तार नहीं हुआ है। आवास सुविधाओं की तीव्र कमी गरीबों को झुग्गी मे झोपड़ियों रहने मजबूर के लिए करती है व लगभग सभी भारतीय शहरों में झुग्गियां विकसित हो गई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में हैं। प्रतिशत लोग मलिन बस्तियों में रहते40 मलिन बस्तियों में बेहद अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ होती हैं। उनके पास तीन-चार झोपड़ियों के बीच में उथला गड्ढा खोदकर बनाए गए दरिद्र शौचालय होते हैं जिनके सामने टाट का 'पर्दा' लटका हुआ होता है। झोपड़ियों के आसपास बच्चे,कहीं भी शौच करने के आदी होते हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में कई नाले और पोखर हैं। ये हमेशा एक गंदे तालाब के बीच में खोदे गए होते हैं।[2]

बेरोजगारी :

भारत में बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर है। भारत में शहरी बेरोजगारी 15 से 25 प्रतिशत है। शिक्षित लोगों में यह और भी अधिक है। यह अनुमान है कि सभी जानकार शहरी बेरोजगार युवाओं में से लगभग आधे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे चार महानगरों में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि शहरी आय ग्रामीण आय से अधिक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की उच्च लागत के कारण वे बहुत कम हैं। शहरी बेरोजगारी का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का भारी संख्या में स्थानांतरण है। अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी मासिक रोजगार सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल बेरोजगारी दर 5.1% है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.0% तथा पुरुषों में 5.2% है। मेक इन इंडिया स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी कई योजनाओं के बावजूद शहरी क्षेत्र के बेरोजगारी की समस्या चिंता का विषय है।[3,8]

परिवहन प्रणाली :

जब ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों की ओर जाते हैं, तो परिवहन व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। ज़्यादा लोगों का मतलब है वाहनों की संख्या में वृद्धि, जिससे यातायात भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाला प्रदूषण होता है। शहरी क्षेत्रों में बहुत से लोग काम पर जाने के लिए गाड़ी चलाते हैं और इससे गंभीर यातायात की समस्या पैदा होती है, खासकर भीड़भाड़ वाले घंटों के दौरान। साथ ही जैसे-जैसे शहर बड़े होते हैं, लोग खरीदारी करने और अन्य सामाजिक ज़रूरतों/इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं, जिससे अक्सर यातायात भीड़भाड़ और अवरोध पैदा होता है। दुनिया भर में 300 मिलियन कार, ट्रक और बसें हैं। पीक ऑवर्स के दौरान, मुख्य जंक्शनों पर भारी ट्रैफिक जाम होता है। पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है जो ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में मदद करती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑटोमोबाइल द्वारा उत्सर्जित होता है।[2]

ध्वनि प्रदूषण श्रवण और गैर-श्रवण दोनों अंगों को प्रभावित करता है। श्रवण संबंधी प्रभाव मनुष्यों में थकान और बहरापन हैं। गैर-श्रवण प्रभाव गति, संचार, झुंझलाहट, कार्यकुशलता में कमी और मनो-शारीरिक विकार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सभी भारतीय शहरों में परिवहन की स्थिति गंभीर है, जबकि मुंबई में अभी भी सबसे अच्छी शहरी परिवहन व्यवस्था है और चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बसों द्वारा उचित रूप से अच्छी सेवा दी जा रही है। हम इस उलझन में क्यों हैं, इसका एक कारण यह है कि शहर के विस्तार की योजना बनाते समय, हम अभी भी गतिविधियों के स्थान के निर्धारक होने वाले आवागमन के समय और दूरी की पश्चिमी अवधारणा का पालन करने के लिए तैयार हैं।[2]

कचरे की समस्या :

शहरी ठोस कचरे में निर्माण सामग्री, प्लास्टिक कंटेनर, अस्पताल का कचरा, रसोई का कचरा आदि शामिल हैं। निर्माण सामग्री और घरेलू ठोस कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है। अस्पताल के कचरे को ले जाते समय उसमें ढक्कन नहीं होते। तीखी गंध हवा को दूषित करती है। शहरी सीवेज में उचित निकास सुविधा नहीं है। जैसे-जैसे भारतीय समाज समृद्ध होता जा रहा है, वैसे-वैसे खतरनाक प्लास्टिक, धातु और पैकिंग वाले कचरे की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले दशक में, जनसंख्या वृद्धि की दर से लगभग दोगुनी दर से कचरा पैदा हुआ। भारत के 3,119 कस्बों और शहरों में से केवल आठ में ही पूर्ण अपशिष्ट जल संग्रह और उपचार की सुविधाएँ हैं। भारत की एक तिहाई आबादी के पास स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच नहीं है। छोटे शहरों और प्रांतीय कस्बों में यह और भी बदतर हो जाता है। हमारे नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग के लिए किफायती किराया देने में असमर्थ हैं।[2]

सीवरेज की समस्याएँ :

भारत के शहरी क्षेत्र अकुशल और अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं से ग्रस्त हैं। भारत का एक भी शहर पूरी तरह से सीवरेज से सुसज्जित नहीं है। इसका कारण यह है कि शहर के अंदर और आसपास के अनधिकृत निर्माण मुख्य प्रणालियों के दायरे से बाहर हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि शहरी आबादी के केवल 38 प्रतिशत लोगों के पास सीवरेज प्रणाली है। मुंबई का ढहता सीवर नेटवर्क एक सदी पुराना है, जिसे ब्रिटिश योजनाकारों ने उस समय स्थापित किया था जब शहर में मछली पकड़ने वाले गाँवों की एक श्रृंखला से अधिक कुछ नहीं था। आज यह बार-बार टूट जाता है। सीवर लाइनें नालियों की ओर जाती हैं, जो सीवेज को सीधे समुद्र में ले जाती हैं, जिससे मुंबई के तट पर लगभग सभी समुद्री जीवन मर जाते हैं। दिल्ली की यमुना एक विशाल सीवर में बदल गई है एवं दिल्ली का 40 प्रतिशत सीवेज अनुपचारित है।[2]

जलापूर्ति :

भारत एक ऐसे चरण में पहुँच गया है जहाँ किसी भी शहर में चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति नहीं होती है। रुकखाली पानी की लाइनों में वैक्यूम बन जाता है जो अक्सर जोड़ों के माध्यम से लीक रुक कर आपूर्ति के कारण- होता है। चेन्नई, हैदराबाद, राजकोट को हर दूसरे दिन आधे घंटे से भी कम समय के लिए नगरपालिका स्रोतों से पानी मिलता है। कई छोटे शहरों में कोई मुख्य जल आपूर्ति नहीं है और वे व्यक्तिगत कुओं, घरेलू खुले कुओं या यहाँ तक कि नदियों जैसे स्रोतों पर निर्भर हैं, जिनमें गर्मियों के दौरान तालाबों में कुछ पानी जमा होता है।[2]

शहर के भीतर, जल निकासी व्यवस्था शायद ही मौजूद है और बड़े इलाकों में हर साल बाढ़ आ जाती है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी और यह अब कई शहरी केंद्रों में एक नियमित घटना है। मुंबई हर मानसून की बारिश के साथ बाढ़ में डूब जाता है और संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। यह समस्या विशेष रूप से सिंधु-गंगा के मैदान के शहरों में गंभीर है। यही हाल वाराणसी और पटना का है। पटना के पूर्वी हिस्से में स्थिति और भी खराब है, जहाँ पूरे मानसून के दौरान पानी भरा रहता है। सबसे खराब स्थिति कटिहार (बिहार) की है, जहाँ शहर की अजीबोगरीब कटोरे जैसी संरचना और जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण मई और जून के महीने में भी पानी के बड़े-बड़े तालाब देखे जा सकते हैं। जो नालियाँ खुली हैं, वे सड़क की सफाई और मानव अपशिष्ट के लिए जमा करने का काम करती हैं। बरसात के मौसम में पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है, जिससे गंदगी फैलती है, अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा होती है और कई बीमारियां फैलती हैं।[2]

पर्यावरण संबंधी समस्याएं:

पर्यावरण प्रदूषण पिछले दशकों की तुलना में आज चिंता का विषय है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई है कि भारत में हर साल 40,000 लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग श्वसन संबंधी बीमारियों, एलर्जी और खांसी से पीड़ित हैं। 1990 के दशक से यह दोगुना हो गया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि 23 भारतीय शहरों ने ऑटो-निकास और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण खतरनाक सीमाओं को पार कर लिया है। इसलिए, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम नहीं है कि वह नियंत्रण करे, बल्कि यह संस्थानों, व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे प्रदूषणकारी कार्यों को रोकने के लिए यथासंभव देखभाल और उपाय शुरू करें। इसलिए, इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। यह वास्तव में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकता है।[2,7,8]

पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट:

शहरीकरण के कारण, पर्यावरण में गिरावट आई है, खासकर पानी, हवा और शोर की गुणवत्ता में। शहरों में अधिक लोगों के आने से, आवास जैसी सुविधाओं की बहुत मांग है। कुछ गैरकानूनी कारखाने और यहां तक कि घर जिनका बुनियादी ढांचा खराब है, इमारतों से निकलने वाले कचरे को सीधे निकटतम नदी या जल संसाधनों में डाल दिया जाता है, जो सीधे पानी को प्रदूषित करते हैं। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जो सीधे नदी में डाले जाते हैं, पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। तेजी से शहरीकरण का एक और दुष्परिणाम वायु प्रदूषण है जो मोटर वाहनों, औद्योगिक विकास और गैरपर्यावरण अनुकूल ईंधन- स्रोतों के उपयोग से उत्सर्जन के कारण भी बढ़ गया है। विभिन्न मानवीय क्रियाओं से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जो पर्यावरण को भी खराब करता है और अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट को निपटानेके लिए स्थान प्रदान करने का दबाव होता है।[2,7,8]

शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट :

शहरीकरण प्रबंधन शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इससे शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। जैसे-जैसे महानगर विकसित शहर बनता जाएगा, भूमि का मूल्य भी बढ़ता जाएगा। आवास प्रावधान उच्च आय वर्ग की जरूरतों को पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसे में, आवास के प्रावधान में समस्या होगी, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए। शहरी गरीबों के लिए आवास अभी भी अपर्याप्त है क्योंकि इन घरों की कीमत निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए बहुत अधिक है। निम्न आय वर्ग के लिए आवास प्रावधान की कमी के कारण शहर में अवैध निवासी बस्तियों का सिलसिला जारी है। इन अवैध किरायेदार बस्तियों में निश्चित रूप से उचित बुनियादी ढांचे की कमी होगी जो शहरी पर्यावरण में कई बाधाएं लाएगी और बाल शिक्षा, अपराध, ड्रग्स, और अन्य सामाजिक समस्याएं पैदा करेगी। निम्न आय वर्ग के लिए आवास समस्या के अलावा, शहरीकरण की प्रक्रिया ने बुनियादी ढांचे और उपयोगिता की मांग को भी बढ़ा दिया है जिसे मौजूदा सुविधाओं से पूरा नहीं किया जा सकता है। नालियों और मलबे के संग्रह का रखरखाव अक्षम है जो अन्य गंभीर समस्याओं जैसे कि अचानक बाढ़ और खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य को जन्म दे सकता है।अचानक बाढ़ का फिर से आना जल निकासी प्रणाली के सतही जल अप्रवाह को रोकने में असमर्थ होने के कारण होता है जो शहरी गतिविधियों की उच्च तीव्रता के साथ बहुत बढ़ गया है।[2]

खराब स्वास्थ्य और बीमारियों का प्रसार :

भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और रहने की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच और उपयोग को प्रभावित करती है। विशेष रूप से झुग्गीझोपड़ी वाले क्षेत्रों में खराब स्वच्छता और अपर्याप्त जल आपूर्ति का अनुभव होता है। शहरी प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे एलर्जी, अस्थमा, बांझपन, खाद्य विषाक्तता, कैंसर और यहाँ तक कि समय से पहले मृत्यु का कारण बनती हैं। शहरीकरण को संक्रामक रोगों के प्रसार से भी जोड़ा गया है, जो कम क्षेत्र में रहने वाले अधिक लोगों के अनुकूल वातावरण में अधिक तेज़ी से फैल सकते हैं। ऐसी बीमारियाँ श्वसन संक्रमण और जठरांत्र संबंधी संक्रमण हो सकती हैं। अन्य संक्रमण ऐसे संक्रमण हो सकते हैं, जिन्हें मनुष्यों में फैलने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। इसका एक उदाहरण डेंगू बुखार हो सकता है।[2]

शहरी अपराध :

संसाधनों की कमी, भीड़भाड़, बेरोज़गारी, गरीबी और सामाजिक सेवाओं और शिक्षा की कमी के मुद्दे अक्सर हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अपराध सहित कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण, दंगे, हमला, चोरी, डकैती और अपहरण जैसे ज़्यादातर अपराध शहरी इलाकों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा, तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में गरीबी से जुड़े अपराध सबसे ज़्यादा हैं। शहरी अपराध के ये कृत्य आम तौर पर शहरों/कस्बों की शांति और सौहार्द को बिगाड़ते हैं।[2]

भारत में शहरी समस्याओं के उपचारात्मक उपाय:

संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल शहरों का निर्माण:

सरकारों को ऐसे कानून पारित करने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल शहरों और स्मार्ट विकास तकनीकों की योजना बनाते हों और उन्हें प्रदान करते हों, यह ध्यान में रखते हुए कि लोगों को असुरक्षित और प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए। यहाँ उद्देश्य संधारणीय शहरों का निर्माण करना है जो सभी शहरी आबादी के लिए बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों और सुरक्षित आवासों को अपनाते हैं। सरकारों को शहरी संसाधनों के संधारणीय उपयोग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और संधारणीय पर्यावरण पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करना चाहिए जैसे

कि हरित अवसंरचना, संधारणीय उद्योग, पुनर्चक्रण और पर्यावरण अभियान, प्रदूषण प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित सार्वजनिक परिवहन और जल पुनर्चक्रण और पुनर्ग्रहण में निवेश।[2]

आवश्यक सेवाओं का प्रावधान:

शहरी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में सभी आबादी को पर्याप्त आवश्यक सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, प्रौद्योगिकी, बिजली और भोजन तक पहुँच हो। यहाँ उद्देश्य रोजगार के अवसर और धन सृजन गतिविधियाँ प्रदान करना और उन्हें लागू करना है ताकि लोग सेवाओं के रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए जीविकोपार्जन कर सकें। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी शिक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, संचार प्रणाली और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है।[2]

अधिक रोजगार सृजन :

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए, निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन से शहरी आबादी के लिए अधिक रोजगार पैदा हो सकते हैं। रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली पर्यावरण के अनुकूल विकास परियोजनाओं में विदेशी और निजी निवेश को सब्सिडी और अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है।[2]

जनसंख्या नियंत्रण:

शहरी क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों को जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरों को कम करने में मदद करने के लिए प्रभावी चिकित्सा स्वास्थ्य क्लीनिक और परिवार नियोजन के लिए अभियान और परामर्श प्रदान करना चाहिए। परिवार उन्मुख चिकित्सा स्वास्थ्य क्लीनिक रोगों और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे शहरी क्षेत्र में नियोजन विकल्पों को सुलभ बनाया जाना चाहिए[2]

निष्कर्ष:

शहरीकरण आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था विकसित होती है; प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में गैरकृषि वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है।जैसे -जैसे शहर विशाल होते जा रहे है , वे स्थानीय सरकारों की प्रशासनिक क्षमता से आगे निकल रहे हैं। तीसरी दुनिया के ज़्यादातर शहर अब अपने निवासियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सबसे बुनियादी सेवाएँ देने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बिजली की माँग इतनी बढ़ गई है जबकि उत्पादन में देरी हो रही है ।समय की माँग है कि दूरदर्शी राष्ट्रीय नीतियों का एक सेट बनाया जाए, जो राष्ट्रीय समानता को प्रोत्साहित करे, एक समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र का विकास करे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता और आय कम से कम शहरी क्षेत्रों के बराबर हो सके। यह स्पष्ट है कि शहरों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका निवेश बढ़ाना और इस प्रकार रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना हो सकता है। शहरी गरीबों के लिये क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रायः लक्षित लाभार्थियों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुँच पाता है। मुख्य रूप से समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों के कारण अधिकांश राहत निधि और लाभ मलिन बस्ती वासियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तीसरी दुनिया के देशों की भारी कर्ज में डूबी सरकारों को नए ऋण की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वे शहरी-पक्षपाती नीतियों को त्याग दें, जिसने उनकी दुविधा में बहुत योगदान दिया है और कृषि नीतियों को अपनाएं जो घरेलू खाद्य

उत्पादन को बढ़ावा देती हैं और आयातित खाद्य पर निर्भरता को कम करती हैं। शहरी विकास से संबंधित कई योजनाएँ/कार्यक्रम: स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत मिशन , स्वच्छ भारत मिशन आदि है जिनका सही क्रियान्वयन इस समस्या को सुलझा सकता है ।

सन्दर्भ:

1. Asthana, D.K, Asthana M. (2013). A Textbook of Environmental Studies, S.Chand and Company Ltd, New Delhi page no 280-285
2. Ali, E. (March 2020).Urbanisation in India: Causes, Growth, Trends, Patterns, Cnsequences & Remedial Measures, DOI:10.13140/RG.2.2.19007.05284
3. Yadav,M.(July-August,2017**).** The Causes and Consequences of Urbanization in Developing countries**,** International Journal of Enhanced Research in Educational Development, ISSN: 2320-8708, Vol. 5 Issue 4,
4. Pathare, R. (16 May 2025). The Economic Times Hindi, Accessed on 20th June 2025
5. The Hindu)June 11, 2025(. New Delhi Accessed on 15th June 2025
6. Chaudhry, M.D. (1989). Population Policy in India. Popul. Environ. 11, 101–121 https://doi.org/10.1007/BF01255727
7. Kumar, A. & Kumar Rai A. (October 2014). Urbanization process, trend, pattern and its concequences in India
8. R.B. Bhagat (May 2018). Urbanization in india, Trend, Pattern and Policy Issues,IIPS Working Paper No 1-23